ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

अक्षय ऊर्जा दे सकती है भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूती

रविवारीय, 16 - 22 अगस्त 2020 वर्ष- दो, अंक-01, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

पूरा हुआ ग्रीन रिवोल्ट के सफल यात्रा का एक वर्ष

रांची :आयोजनों की भाषा में किसी के अनवरत एक वर्ष पूरे होने को कॉटन जुबली कहते हैं। 15 अगस्त 2020 को ग्रीन रिवोल्ट के प्रकाशन का भी कॉटन जुबली पूरा हुआ। साल 2019 के स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हम तीन लोगों ने मिलकर रांची प्रेस क्लब से ग्रीन रिवोल्ट साप्ताहिक समाचार पत्र का लोकार्पण किया था। बगैर किसी तामझाम के रांची के कुछेक पर्यावरणप्रेमी मित्रों की उपस्थिति में इसका विमोचन किया गया। जिसमें भुंगरू नाम से जल संरक्षण में सदैव काम कर रहे मित्र रथिन भद्रा, कांके डैम बचाओ अभियान के प्रमुख अमृतेश पाठक, पर्यावरणविद् मंगला प्रसाद मिश्र, पशु चिकित्सक भूषण प्रसाद, पत्रकारिता के कुछेक छात्र और मित्र प्रमुख थे। ग्रीन रिवोल्ट संभवतः झारखंड का पहला पर्यावरण, वन जल संरक्षण और कृषि को समर्पित समाचार पत्र है। प्रकाशन के समय से ही वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर सभी मित्रों ने हमारे इस प्रयास को सराहा और

15 अगस्त 2019 का रांची प्रेस क्लब में ग्रीन रिवोल्ट के विमाचन की तस्वीर

उत्साहवर्द्धन के साथ ही सामग्रियों तक को उपलब्ध कराया। इसी का नतीजा है कि बहुत ही कम साधनों में भी हमने एक साल का सफर बहुत ही सफलता पूर्वक पूरा किया। ग्रीनरिवोल्ट ने उत्तरोत्तर प्रगति की अपने सामग्रियों, पाठकों की रूचियों और साज सज्जा में हम सुधार करते गये जिसके कारण सुधि पाठकों की संख्या भी लगातार बढती गयी जिसमें दिल्ली, लखनउ, मुंबई तक के पाठक हैं। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अजय कुमार जी का सराहनीय योगदान मिलते रहा है। आज वेब पोर्टलों के दौर में अखबार का अनवरत प्रकाशन एक चुनौती का काम है, लेकिन हम तीन लोगों ने (वरिष्ठ पत्रकार एन के मुरलीधर, पशु अधिकारों के लिये लंबे समय तक काम कर चुके मित्र मनोरंजन सिंह और स्वयं मैं) अथक परिश्रम से ग्रीन रिवोल्ट की यात्रा को जारी रखा।

आज यह जान कर सबों को प्रसन्नता होगी कि ग्रीन रिवोल्ट के प्रकाशन के साथ ही झारखंड के लोगों में वृक्ष लगाने से लेकर , जल संरक्षण, नदियों तालाबों को बचाने के प्रति सजगता बढ़ी है और यही हमारा मूल उद्देश्य भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में पर्यावरण प्रेमी और चैतन्य लोग ग्रीन रिवोल्ट से जुड़ते रहेंगे और हमारा कारवां बढता रहेगा।

सीसीएल की सहायता से लातेहार के 167 आंगनबाड़ी केन्द्र बनेंगे मॉडल केन्द्र

9.4 करोड़ की लागत से 5 जिलों के 628 आंगनबाड़ी केन्द्र का सीसीएल करेगा कायाकल्प

सीसीएल एवं लातेहार जिला प्रशासन के बीच आज 167 आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडलआंगनबाड़ी केन्द्र विकसित करने के लिए उपायुक्त जिशान कमर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित करने के लिए समझौता पत्र पर जिला प्रशासन की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती प्रीति सिन्हा एवं सीसीएल की ओर से महाप्रबंधक (सीएसआर) श्री ए के सिंह ने हस्ताक्षर किए। सीसीएल एवं प्रशासन के बीच समझौत पत्र होने के बाद लातेहार जिले के 167 आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय सहयोग सीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सीसीएल के इस विकसित मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र से बच्चे एवं महिलाएं अवश्य लाभान्वित होंगे।

अवैध रेत खनन को रोकने के लिए समिति ने दिए सुझाव

संवाददाता

न्यायमूर्ति एस.वी.एस. राठौड़ ने अवैध रेत खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष 13 अगस्त, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पहले समिति को गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेत खनन के मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था।

समिति ने सिफारिश की कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) को बहुत सावधानी से तैयार करने की आवश्यकता है। इनका प्राकृतिक तौर पर सर्वेक्षण और फिर से अध्ययन किया जाना चाहिए। चूंकि रेत जमाव एक लगातार चलने वाला मुद्दा है, इसलिए उन्हें नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। लीज डीड देते समय, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मापदंडों जैसे कि रेत जमाव और इसकी पुनःपूर्ति, कटाव वाले क्षेत्र,

आधारिक संरचनाओं से दूरी पर विचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तंत्र होना चाहिए कि वास्तविक खनन गतिविधि स्वीकृत खनन योजना और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के अनुरूप हो। विभागीय निरीक्षण की वैधानिक प्रणाली के अलावा, विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक पर्यावरण आडिट की एक प्रणाली अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

इसके अलावा, खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बहाली के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए। रॉयल्टी का एक हिस्सा पर्यावरण बहाली कोष (एनवायरनमेंट रेस्टोरेशन फंड) के रूप में रखा जाना चाहिए।

रेत का भंडारण गोदाम नदी तट से कम से कम 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। समिति ने कहा कि अन्यथा पट्टाधारक द्वारा भंडारण की आड़ में अवैध खनन किया जा सकता है।

येल यूनिवर्सिटी ने फाइब्रोसिस की खोजी नयी दवा, कोविड-19 के इलाज में हो सकती है सहायक

एजेंसियां

येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गयी 'सोबेट्रियम' नामक यह दवा कोविड- 19 के मरीजों में होने वाले एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की रोकथाम और उपचार में कारगर हो सकती है। येल पल्मोनोलॉजिस्ट नफ्ताली कर्मिसकी ने कुछ साल पहले इस दवा पर काम करना शुरू किया था। जिससे लंग फाइब्रोसिस का इलाज किया जा सके। पर वर्तमान शोध से पता चला है कि यह दवा कोविड-19 के इलाज में भी कारगर हो सकती है। अब डॉ नफ्ताली और उनकी टीम जल्द से जल्द इस दवा का क्लीनिकल ट्रायल करने पर काम कर रही है। यह दवा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (एआरडीएस) की रोकथाम और उपचार में भी कारगर है।

गौरतलब है कि कोरोनावायरस के चलते गंभीर रूप से बीमार मरीजों में श्वशन सम्बन्धी विकार उत्पन्न हो जाता है। जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में मरीज के फेफड़े फूल जाते है और उनमें फ्लूइड जमा हो जाता है। जिस वजह से मरीजों के सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।परिणामस्वरूप उन्हें गहन देखभाल और वेंटिलेटर पर रखने की जरुरत पड़ जाती है। कमिंसकी ने बताया कि चूहे पर किये अध्ययन में यह दवा 'सोबेट्रियम' अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुई है। हालांकि कोविड-19 के मरीजों पर एआरडीएस के लिए इस दवा का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है।

बीएयू के शोध वैज्ञानिकों ने कहा: सब्जियों का विदेशों में निर्यात किसान हित में बेहतर पहल

अजय कुमार

रांची : झारखण्ड राज्य में उत्पादित सब्जी फसलों को विदेशों में निर्यात किये जाने से किसान हर्षित है। वहीं बीएयू के शोध वैज्ञानिकों ने इसे सरकार का बेमिसाल पहल बताया और काफी उत्साहित है। निदेशक अनुसंधान डॉ. अब्दुल वदूद ने इसे झारखण्ड के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय पहल बताया है।

उन्होंने बताया की दशकों से झारखण्ड में किसानों द्वारा सरप्लस सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन बेहतर बाजार के आभाव में किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा था। राज्य में उपजी सब्जियों की खेप दुबई भेजे जाने के कदम से किसानों में बेहतर लाभ की आस जगी है।

इस पहल से किसानों में नई-नई सब्जी किस्मों और तकनीकों को अपनाने की रुचि बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिक में नई सोच के साथ बेहतर तकनीकों को विकसित करने की दिशा में नए

राष्ट्रीय तीसी कार्य समुह की वार्षिक बैठक में बीएयू वैज्ञानिकों ने भाग लिया
बीएयू सहित देश के करीब 100 तीसी फसल विशेषज्ञ हुए शामिल

रांची क आईसीएआर की भारतीय तेलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईओआर), हैदराबाद ने शुक्रवार को वेबीनार के माध्यम से राष्ट्रीय तीसी कार्य समुह की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. बैठक में आईसीएआर-अखिल भारतीय समन्वित तीसी शोध परियोजना से जुड़े शोध केन्द्रों के 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया. बैठक की अध्यक्षता आईसीएआर महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा ने की. उन्होंने तिलहन फसलों में तीसी (अलसी) को दूसरी महत्वपूर्ण फसल बताया. उन्होंने वैज्ञानिकों को उन्नत किस्मों, बेहतर शस्य प्रणाली एवं रोग व कीट प्रबंधन से तीसी की खेती को बढावा देने पर जोर दिया.

राष्ट्रीय परियोजना अन्वेंशक डॉ जीपी दीक्षित ने तेलहनी फसल तीसी पर देश भर में किये जा रहे शोध उपलब्धियों का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश किया. आईआईओआर के राष्ट्रीय निदेशक डॉ ए विष्णु वर्धन रेड्डी ने तीसी की उन्नतशील प्रजातियों का विकास की रणनीति पर प्रकाश डाला. बीएयू, रांची केंद्र के परियोजना अन्वेंशक डॉ सोहन राम ने बीएयू द्वारा विकसित दो किस्मों 'दिव्या व प्रियम' तथा देश के अन्य केन्द्रों के 150 जनन द्रव्य का शोध आकलन, प्रजनक बीज उत्पादन तथा आदिवासी किसानों के खेतों में तकनीकी उपलब्धियों को पेश किया. इससे जुड़े दो वैज्ञानिक डॉ परवेज आलम ने तीसी की शस्य प्रणाली तथा डॉ एमके वर्णवाल ने कीट एवं रोग प्रबंधन के शोध को बताया. बीएयू द्वारा विकसित दो किस्मों 'दिव्या व प्रियम' का राष्ट्रीय स्तर बेहतर प्रदर्शन पाया गया है. इन किस्मों को केन्द्रीय बीज प्रमाणन एजेंसी से अनुसंशित तथा नेशनल सीड चैन में शामिल किये गया है. तीसी में मौजूद ओमेगा- 3 की मात्रा कोलेस्ट्रोल, हृदय एवं गठिया रोग में लाभदायक तथा लीग्नेन नामक तत्व कैंसर अवरोधी होता है. बाजार में ज्यादा मांग और बेहतर लाभ को देखते हुए प्रदेश में तीसी खेती में काफी संभावनाएँ हैं।डॉ अब्दुल वदूद ने राज्य में अधिक मुनाफा वाली तेलहनी फसल तीसी की खेती पुनः प्रचलित होने की बात कही . बीएयू की 'दिव्या व प्रियम' के बेहतर प्रदर्शन वैज्ञानिक दल को बधाई दी है.

शोध - प्रसार कार्यक्रमों को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के इस साकारात्मक सोच और पहल ने प्रदेश में संभावनाओं के अनेकों द्वार खोल दिये है।

झारखण्ड का नया प्रतीक चिन्ह हुआ जारी

एजेंसियां

- **यह प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है :श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल**
- **प्रतीक चिन्ह झारखण्ड की भावना को प्रतिविम्बित करता है: हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री**

आर्यभट्ट हॉल रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रबिन्द्र नाथ महतो व राज्य सभा सांसद शिबू सोरेन ने झारखण्ड के नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया ।

झारखंड के नये प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर राज्य के महान वीर सपूतों को नमन। राज्यवासियों को झारखण्ड के नए प्रतीक चिन्ह की बधाई। यह प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है। इसमें राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक खनिज संपदा को समाहित किया गया है, जो अद्भुत है। उपरोक्त बातें राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नये प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर आर्यभट्ट सभागार में कही।

झारखण्ड सामूहिकता में विश्वास रखता है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि देश की आजादी में झारखण्ड के भूमि पुत्रों ने लंबा संघर्ष किया। हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। आजादी के बाद से नए भारत के नवनिर्माण में झारखण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां के श्रमिक अपने श्रम से अन्य राज्यों में समृद्धि ला रहें हैं। आदिवासी बहुल यह राज्य सदैव सामूहिकता में यकीन रखता है। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह बदलाव का सारथी है। प्रतीक चिन्ह झारखण्ड की भावना को प्रतिविम्बित करता है।

प्लास्टिक एक भयावह वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र में एसोशिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है। आपके 300 से अधिक लेख तथा 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं। के. एन. भाल नामित पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, विज्ञान परिषद् प्रयाग शताब्दी सम्मान, राजभाषा भूषण पुरस्कार सहित अनेक अलंकरणों से सम्मानित डॉ. मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

.....गतांक से आगे दूसरी किश्त

लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेट्स वे प्लास्टिक हैं जो एक बार ठंडा होकर सख्त बन जाने के बाद उस आकार को बनाए रखते हैं और अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकते। ये कठोर और टिकाऊ होते हैं। इन्हें ऑटोपार्ट्स, वैमानिक पार्ट्स, और टायरों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलियूरिथेन्स, पॉलीस्टर्स, इपॉक्सी रेज़िन्स और फीनोलिक रेज़िन्स इसके उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक्स वे प्लास्टिक हैं जो गरम करके नरम किए जा सकते है और अपने मूलरूप में वापस लौट सकते हैं। इन्हें आसानी से ढ़ाला जा सकता है। इसके उदाहरणों में पॉलीईथाइलिन, पॉलिप्रोपाईलिन, पॉलिविनाइल क्लोराडड शामिल हैं। इनके अलावा प्लास्टिक को जैव निम्नीकरणीय, इंजीनियर और इलास्टोमर प्लास्टिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। कुछ सामान्य प्लास्टिक इस प्रकार हैं;

प्लास्टिक में पाए जाने वाले कई योगज (additives) जैसे कि थैलेट्स (phthalates), एडिपेट्स (adipates), और ऐल्काइलफीनॉल्स (alkylphenols) विषाक्त माने जाते हैं। विनाइल क्लोराइड, जो कि पीवीसी पाइप के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, एक कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत है। उदाहरण विभिन्न प्लास्टिक का उपयोग

- पॉलीइथाइलीन टेरेथैलेट (पीईटी) - सोडा की बोतलें, रस्सी, कालीन फाइबर
- उच्चघनत्व पॉलीथीन - दूध की बोतलें, पानी के पाइप, 3-डी प्रिंटर रेशा
- पॉलीविनाइल क्लोराइड - सीवर पाइप, विद्युत केबलों के लिए इन्सुलेशन, फ़र्श
- न्यूनघनत्व पॉलीइथाइलीन - खेल का मैदान स्लाइड, प्लास्टिक की चादरें
- पॉलीप्रोपाइलीन - प्रयोगशाला के उपकरण, दही के बर्तन , फ्लिप-टॉप लेड्स
- पॉलीस्टाइरिन - डिस्पोजेबल कॉफी कप, सुरक्षा पैकेजिंग, कटलरी
- नायलॉन - पैराशूट, टूथब्रश, ब्रिसल्स, स्टॉकिंग्स

- पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट (PET/PETE)
- पॉलीस्टाइरीन (स्टाइरोफोम)
- पॉलीविनाइलक्लोराइड (PVC)
- पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलीन (टेफ्लॉन)
- पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड
- पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन
- पॉलीप्रोपाइलीन (PP)

प्लास्टिक ज्यादातर रासायनिक तौर पर निष्क्रिय होते हैं। ये अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए न ये सड़ते हैं, न गलते हैं। ये लम्बी अवधि तक जस का तस पड़े रहते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का निपटान आज एक कठिन और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्न बन गया है।

प्लास्टिक कई मायनों में बेहद उपयोगी है और वैश्विक पॉलीमर उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इनका उत्पादन और निपटान पृथ्वी पर जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक आम तौर पर 500-1000 वर्षों में नष्ट होता है। इसके निर्माण के दौरान कई खतरनाक रसायन उत्सर्जित होते हैं जो कि मानव और अन्य जीवों में खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं। प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक जहर इथाइलीन ऑक्साइड, ज़ायलीन और बेंजीन का पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव होता है। इससे निपटना आसान नही होता है और यह जीवधारियों को स्थायी नुकसान पहुँचा सकता है।

जारी ....

(इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार)

सोना दहायेल जाये कोयला पर छापा?

उपरोक्त देशज शीर्षक का मतलब है कि बहुमूल्य चीजें बर्बाद हो रही हैं और हम कोयले को बटोरने में लगे हुये हैं? केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में कोयला खनन की अनुमति दी है जहां पर्यावरण से लेकर वन्य जीवों और जलस्त्रोतो का भयंकर विनाश होगा। ये सब सिर्फ कोयले के लिये? अगर यहां हम तुलना करके देखें तो इस खनन से जितनी बर्बादी जंगलों ,नदियों और जल की होगी उसके सामने कोयला बहुत ही तुच्छ चीज है। आखिर हम कोयले जैसी चीज के लिये इतनी बर्बादी करने पर क्यों तुले हुये हैं।

आज जब कोयला आधारित उद्योगों को कई देश खत्म कर रहे हैं उस दौर में भारत में जंगलों को उजाड़ कर, नदियों और पर्यावरण को बर्बाद कर कोयला निकालना कहीं से भी अक्लमंदी नहीं है।

सरकार की यह सोंच कि *कोयले की उपयोगिता खत्म होने से पहले ही जमीन से जितना संभव हो उतना कोयला निकाल कर उपयोग कर लेना है* एक आत्मघाती कदम है। इस आतुरता में उपयोगिता कितनी होगी यह तो किसी को नहीं पता, पर कोयला खनन में विदेशी कंपनियों तक के आ जाने के बाद यहां जंगलों, पहाड़ों, नदियों, वन्य जीवों, पर्यावरण , कृषि योग्य भूमि का जो विनाश होगा उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पायेंगे। इस पर केंद्र सरकार को एक बार विचार अवश्य करना चाहिये।

छत्तीसगढ में हसदेव अरण्य इलाके में जिसें कोयला खनन के लिये चुना गया है उसका 87 प्रतिशत हिस्सा घने जंगलों, नदियों, पहाड़ों और वन्य जीवों से भरा हुआ है । खनन शुरू हुआ तो यह सब एक झटके में ही बर्बाद हो जायेगा और इसकी भरपाई हम कुछ भी कर लें कभी नहीं कर पायेंगे। हसदेव जैसे क्षेत्र झारखंड, बंगाल, और महाराष्ट्र में भी हैं जहां खनन से जंगलों के अलावा हजारो आदिवासियों और वन्य जीवों के आसियाने भी उजाड़ दिये जायेंगे। अब तक इन इलाकों में जंगलों, वन्य जीवों और रह रहे आदिवासियों के संरक्षण के कारण कोयला खनन पर रोक थी, लेकिन केंद्र सरकार की यहां से एकाएक कोयले निकालने की आतुरता समझ से परे है।

यहां यह जान लेना आवश्यक है कि साल 19-20 में आयात और अपने यहां का कोयला उत्पादन मिलाकर सरप्लस था। यानि आवश्यकता से तकरीबन आठ करोड़ टन ज्यादा था। ऐसे में बहुमूल्य वन संपदा, पर्यावरण, वन्य जीवों को बर्बाद कर वर्तमान में उर्जा के आउटडेटेड हो रहे साधन कोयले को निकालना आत्मघाती कदम के सिवा के कुछ नहीं।

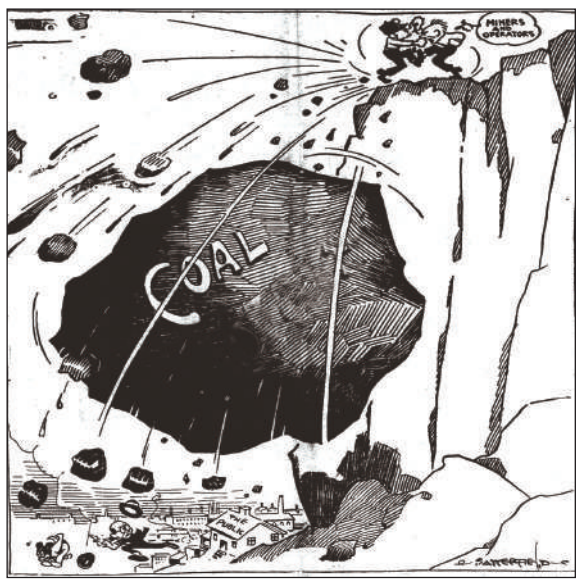

हर साल 47 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य का खाद उत्पादन करते हैं समुद्री पक्षी

शोधकर्ताओं का कहना है कि पक्षियों का मल जिसे पोप, या गुआनो के रूप में भी जाना जाता है। गुआनो उर्वरक के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। गलबेड और पेलिकन जैसी समुद्री पक्षियों की प्रजातियों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। जब इनके संरक्षण की बात आती है तो लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं। लोगों की इनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पक्षियों का मल जिसे पोप, या गुआनो के रूप में भी जाना जाता है। गुआनो उर्वरक के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह उर्वरक तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी सालाना कीमत 470 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपए 35,185,375,000) से अधिक हो सकती है। लोगों को होने वाले इस प्रत्यक्ष लाभ को देखते हुए, समुद्री पक्षी के महत्व के बारे में पता चलता हैं। इनकी घटती आबादी से पारिस्थितिक तंत्र सहित अरबों का आर्थिक नुकसान हो सकता हैं। यह शोध ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोलुशन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

वर्तमान में कुछ समुद्री पक्षियों की प्रजातियां व्यावसायिक तौर पर उर्वरक या गुआनो का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जा रहीं हैं। बाकी पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं जहां उनके गुआनो को जमा किया जाता है। क्योंकि यह वैज्ञानिक और जैविक रूप में महत्वपूर्ण है, इसलिए समुद्री पक्षियों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में अहम भूमिका निभाई जाती है। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के समुद्री पक्षियों की आबादी के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किया है। इसमें ऐसी पक्षियां शामिल हैं जो कि व्यापार के लिए गुआनो का उत्पादन करती हैं।

देश के लिए कितनी फायदेमंद है गन्ने से बनी ऊर्जा !

भारत सरकार ने 2030 तक इथेनॉल से गैसोलीन ब्लेंडिंग की दर को 6 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कई नीतियां पेश की हैं।

शोध के अनुसार गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल का उत्पादन जल और ऊर्जा संसाधनों को अधिक सस्टेनेबल बना सकता है। साथ ही इससे अन्य पोषक फसलों के लिए भूमि और जल की उपलब्धता भी बनी रहेगी। यदि भारतीय ऊर्जा उद्योग बायोइथेनॉल फीडस्टॉक के रूप में गुड़ अथवा खांड का उपयोग जारी रखेगा तो उससे सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल और जमीन की जरुरत पड़ेगी। जबकि इसके विपरीत यदि उद्योग इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ने के रस का उपयोग करता है, तो बिना अतिरिक्त भूमि और जल के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा।

भारत में बढ़ी पवन और सोलर ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी

निशांत सक्सेना

कोयले पर कम होती निर्भरता का संकेत देते हुए 2020 की पहली छमाही में भारत में विंड और सोलर एनर्जी उत्पादन कुल ऊर्जा उत्पादन का दस प्रतिशत हो गया

विंड और सोलर ने 2015 से कोयले के पांच प्रतिशत अंक बाजार में हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। 2015 में कोयला की हिस्सेदारी 37.9% से गिरकर 2020 की पहली छमाही में 33.0% हो गई, क्योंकि पवन और सौर 4.6% से बढ़कर 9.8% हो गए।

भारत का परिवर्तन और भी नाटकीय था: 2015 में कुल उत्पादन का 3% से पवन और सौर शेयर 2020 की पहली छमाही में 10% हो गया; उसी समय, कोयले का हिस्सा 77% से गिरकर 68% हो गया। कोयले पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए, पवन और सौर वैश्विक औसत के अनुरूप बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष H1-2019 की इसी अवधि की तुलना में H1-2020 में पवन और सौर उत्पादन में(विश्व स्तर पर 14% की तुलना में), भारत में 13% की वृद्धि हुई और इसका मतलब है कि पवन और सौर एनर्जी से भारत की 9.7% बिजली (विश्व स्तर पर 9.8% की तुलना में) उत्पन्न हुई। इस बीच, ल्1-2020 में भारत का कोयला उत्पादन 14% गिर गया (H1-2019 की तुलना में)। भारत की बिजली की कोयले की हिस्सेदारी 2015 में 77% से घटकर 2020 की पहली छमाही में 68% हो गई है, साथ ही विंड और सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी 3.4% से बढ़कर 9.7% हो गयी।

जहां अमेरिका और यूरोप ने अपने कोयले के उपयोग को कम किया है,वहीं वैश्विक कोयला उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ में कोयला उत्पादन में गिरावट का मतलब है कि वैश्विक कोयला उत्पादन का उनका हिस्सा 2015 में 23% से घटकर H-20-2020 में 12% हो गया है जैसा कि कुछ पर्यवेक्षकों को उम्मीद थी भारत और अन्य एशियाई देशों में कोयले का उपयोग नहीं बढ़ रहा है । इसका मतलब है कि इस साल वैश्विक कोयला उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 2019 में 50% से बढ़कर 54% हो गई जबकि 2015 में यह44% थी।

डेबर जोन्स, एम्बर में वरिष्ठ बिजली विश्लेषक ने कहा: ''दुनिया भर के देश अब एक ही रास्ते पर हैं - कोयले और गैस से चलने वाले पावर प्लांटों से बिजली को बदलने के लिए विंड टरबाइन और सोलर पैनल का निर्माण। लेकिन जलवायु परिवर्तन को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का एक भी मौका होने के लिए इस दशक में कोयले के उत्पादन में हर साल 13% की कमी आनी चाहिए। यह तथ्य कि एक वैश्विक महामारी के दौरान कोयला उत्पादन अभी भी केवल 8% कम हो गया है, दिखाता है कि हम अभी भी लक्ष्य से कितने दूर हैं। हमारे पास इसका समाधान है, जो काम कर रहा है, लेकिन यह अभी पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है।

2020 की पहली छमाही में कोयला उत्पादन में 8.3% की गिरावट आई। इसमें से दो-तिहाई 31% अमेरिका में बड़ी गिरावट और 32% यूरोपीय संघ के कारण था। 2019 में 3% की गिरावट के बाद भी भारत की बड़ी गिरावट 14% हुई। द2-2020 में बिजली की अधिक मांग के कारण चीन में कोयला से उत्पादित बिजली में सिर्फ 2% की कमी आयी जो सबसे कम थी ।वियतनाम में कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन कोयला उत्पादन में वृद्धि पनबिजली उत्पादन में गिरावट के बराबर थी।

विंड और सोलर कोविड-19 के प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर 3% की गिरावट के बावजूद वर्ष 2020 की पहली छमाही में वैश्विक बिजली के 10% की -उच्च बाजार हिस्सेदारी तक पहुँच गए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है । पिछले साल के मुकाबले इसमें 14% का इजाफा हुआ है। विंड और सोलर इन दोनों में इजाफे के पीछे सबसे खास वजह है कोयला उत्पादन में 1990 के बाद से पहली बार 2020 के पहले छह महीनों में आयी सबसे ज्यादा गिरावट। इस-ाका मतलब है कि इस साल, पहली बार, दुनिया के कोयला बिजली संयंत्र या थर्मल पॉवर प्लांट्स अपनी क्षमता से आधे से भी कम पर चले हैं ।

वैश्विक बिजली उत्पादन में विंड और सोलर का हिस्सा 2019 में 8.1% से बढ़कर ल्1-2020 में 9.8% हो गया है; 2015 में पेरिस क्लाइमेट समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के वक़्त से उनका हिस्सा 4.6% से अधिक हो गया। विंड और सोलर ने लगभग न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रो जितनी CO2- मुक्त शक्ति उत्पन्न करी, जिसने H1-2020 में 10.5% वैश्विक बिजली उत्पन्न की और जिसका हिस्सा 2019 से अपरिवर्तित रहा।

- कई प्रमुख देश अब विंड और सोलर से अपनी बिजली का दसवां हिस्सा उत्पन्न करते हैं: चीन (10%), अमेरिका (12%), भारत (10%), जापान (10%), ब्राजील (10%) और तुर्की (13%)। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन क्रमशः 21% और 33% के साथ और भी अधिक; यूरोपीय संघ के भीतर, जर्मनी 42% तक बढ़ गया। रूस अब तक विंड और सोलर से दूर हटा हुआ सबसे बड़ा देश है, इसकी विंड और सोलर से सिर्फ 0.2% बिजली उत्पन्न होती है।
- H1-2019 की तुलना में 2020 की पहली छमाही में वैश्विक कोयला उत्पादन 8.3% गिर गया। यह 2019 में 3% की साल-दर-साल की गिरावट से निम्नानुसार है, जो कम से कम 1990 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रही। H1-2020 में गिरावट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के साथ-साथ बढ़ती विंड और सोलर एनर्जी के कारण H1-2020 में बिजली की मांग वैश्विक स्तर पर 3.0% गिर गई। हालाँकि कोविड-19 के कारण H1-2020 में 70% कोयले की गिरावट का कारण कम बिजली की माँग को माना जा सकता है, लेकिन बढ़े हुए विंड और सोलर उत्पादन के लिए 30% को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ, क्रमशः 31% और 32% की गिरावट के साथ, कोयले को कम करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। चीन में कोयला केवल 2% घटा, जिसका मतलब है कि वैश्विक कोयला उत्पादन का हिस्सा इस साल अब तक बढ़कर 54% हो गया, 2019 में 50% और 2015 में 44% से ऊपर।
- विंड और सोलर ने 2015 से कोयले के पांच प्रतिशत अंक मार्केट शेयर हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। कोयला का हिस्सा 2015 में 37.9% से घटकर 2020 की पहली छमाही में 33.0% हो गया, क्योंकि विंड और सोलर एनर्जी 4.6% से बढ़कर 9.8% हो गए। भारत का परिवर्तन और भी बड़ा था: विंड और सोलर एनर्जी का हिस्सा 2015 में कुल उत्पादन के 3% से 2020 की पहली छमाही में 10% हो गया; साथ ही, कोयले का हिस्सा 77% से गिरकर 68% हो गया। पहली बार, दुनिया का कोयला बेड़ा इस वर्ष अपनी क्षमता से आधे से भी कम पर चला।
- वैश्विक बिजली संक्रमण 1.5 डिग्री के लिए ऑफ-ट्रैक है। इस दशक में कोयले को हर साल 13% गिरने की जरूरत है, और एक वैश्विक महामारी के होने के बावजूद भी 2020 की पहली छमाही में कोयला उत्पादन केवल 8% घटा है। IPCC के 1.5 डिग्री परिदृश्य से पता चलता है कि 2030 तक कोयला वैश्विक स्तर पर ल्1-2020 में 33% से घटकर केवल 6% रह जाएगा। सभी परिदृश्यों में क्ढउ दिखाता है कि अधिकांश कोयले का प्रतिस्थापन विंड और सोलर के साथ है।

उष्णकटिबंधीय वनों में कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव

दयानिधि

उष्णकटिबंधीय वनों की मिट्टी में सीओ2 की एक छोटी सी वृद्धि भी वैश्विक जलवायु के परिणामों के साथ वायुमंडलीय सीओ2 सांद्रता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उष्णकटिबंधीय वनों की मिट्टी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो कि सदी के तापमान के लिए लगाए गए अनुमानों की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक सीओ2 जारी कर रही है। जबकि इन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने वालों के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में सीओ2 का समावेश (सिंक) और बाहर निकलना पृथ्वी के जटिल कार्बन चक्र का एक प्रमुख भाग है। इससे कार्बन चक्र का संतुलन लगभग बना रहता है। पर अब हम लोग इस पर जीवाश्म ईंधन को जलाकर लगातार कार्बन प्रदूषण में बढ़ोतरी कर दबाव बढ़ा रहे हैं।

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जियोसाइंसेज के एक शोधकर्ता एंड्रयू नॉटिंघम ने बताया कि उष्णकटिबंधीय मिट्टी में मौजूद कार्बन पहले की तुलना में अधिक है, जो तापमान बढ़ाने के लिए अधिक संवेदनशील है। यह अध्ययन नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यहां तक कि उष्णकटिबंधीय वनों की मिट्टी में सीओ2 की एक छोटी सी वृद्धि भी वैश्विक जलवायु के परिणामों के साथ वायुमंडलीय सीओ2 सांद्रता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। दुनिया भर में मिट्टी के माध्यम से हर साल कार्बन चक्र की मात्रा मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से 10 गुना अधिक है।

यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल साइंस के शोधकर्ता, एरिक डेविडसन ने कहा कि यदि एक प्रतिशत कार्बन भी सिंक होने के बजाय बाहर निकल जाता है तो, यह मानव निर्मित कार्बन उत्सर्जन के लगभग दस प्रतिशत के बराबर होगा।

पृथ्वी की औसत सतह का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर केवल 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो, यह सूखा, हीटवेव और भयंकर तूफान के खतरों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। समुद्रों का बढ़ता जलस्तर इसे और अधिक विनाशकारी बना देगा। प्रयोगों के लिए नॉटिंघम और उनके सहयोगियों ने पनामा के बारो कोलोराडो द्वीप पर निर्जन वन के एक हेक्टेयर भू-भाग में तापक छड़ें रखीं। इन छड़ों ने दो साल की अवधि में मिट्टी को केवल 1 मीटर (तीन फीट) की गहराई तक 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। मिट्टी का तापमान आमतौर पर हवा के तापमान से एक डिग्री अधिक गर्म होता है। हालांकि इस तरह के प्रयोग उच्च अक्षांश के जंगलों में किए गए हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह का कोई भी प्रयोग अभी तक नहीं किया गया था।

बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी से संभावित कार्बन रिसाव को ध्यान में रखने वाले जलवायु मॉडल ने सैद्धांतिक गणनाओं पर भरोसा किया है। जो परीक्षण की तुलना में आउटपुट को कम आंकते हैं। अध्ययन का अनुमान है कि अगर 2100 से कुछ समय पहले दुनिया की सभी उष्णकटिबंधीय वनों की मिट्टी दो साल की अवधि के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, तो यह 6500 करोड़ (65 बिलियन) टन कार्बन लगभग 24000 करोड़ (240 बिलियन) टन के बराबर सीओ2 वायुमंडल में जारी करेगी।

नॉटिंघम ने कहा कि यह मानव-जनित स्त्रोतों से मौजूदा वार्षिक उत्सर्जन से छह गुना अधिक है। इसे कम करके आंका जा सकता है, क्योंकि हमने अपने दो वर्षों के प्रयोग में पाया कि आगे बड़े नुकसान होने के आसार हैं। शोधकर्ताओं ने कहा किसी भी प्रयोग के आधार पर कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, फिर भी हमने सावधानी बरती है। अब तक वनों और महासागरों ने मानव गतिविधि से लगभग आधे से अधिक कार्बन उत्सर्जन को लगातार अवशोषित किया है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनमें कहा गया है कि, कुछ जंगलों द्वारा सीओ 2 कम अवशोषित की जा रही है। जब पेड़ों को काट दिया जाता है, तब संग्रहीत सीओ2 भी निकल जाती है।

ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच के अनुसार पिछले साल, हर छह सेकंड में फुटबॉल के मैदान के बराबर वनों के आवरण को नष्ट किया गया। जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर (14,500 वर्ग मील) के बराबर है।

ट्रैक्टर की खराब जुताई से घट जाती है मक्के की पैदावार

कई साल से ट्रैक्टर से जुताई कर रहे राजस्थान के किसानों ने अब हल से खेती करनी शुरू कर दी है अब इक्कीसवीं सदी में बैलों और हल से जुताई गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं, लेकिन राजस्थान के दो जिलों के लगभग दो दर्जन से अधिक गांवों में ग्रामीण अपने खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग कर रहे हैं। यह सिलसिला पिछले दो साल से चल रहा है। हालांकि इसके पहले वे भी ट्रैक्टरों के माध्यम से ही अपने खेतों की जुताई करते आए थे। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि इस समय मक्के की बुवाई चल रही है और स्थानीय लोगों ने यह महसूस किया कि ट्रैक्टर से जुताई के मुकाबले जब हल से जुताई होती है तो मक्के का उत्पादन अधिक होता है। इसलिए वे या तो खुद ही बैलों को जोत कर जुताई रहे हैं या मजदूरों से हल से जुताई करवा रहे हैं।

इसका मूल कारण है कि ट्रैक्टर से बहुत ही खराब तरीके से जुताई होती है। इसमें खेतों में जगह बहुत अधिक छोड़ दी जाती है, वहीं कहीं वह अधिक गहरा जोत देता है तो कहीं ऊपर। और इसके अलावा उसके जोतने की दूरी आधा फीट के बराबर होती है। जबकि इतनी ही दूरी में हल से दो बार जुताई हो जाती है जिससे मक्के की पैदावार बढ़ जाती है।

रासायनिक स्त्राव से एक दूसरें को आकर्षित कर झुंड बनाती हैं टिड्डियां

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने चार टिड्डियों को एक पिंजरे में एक साथ रखा और पाया कि टिड्डियां एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए केमिकल छोड़ रहे थे

टिड्डियां दुनिया के कई हिस्सों में फसलों को तबाह कर रही हैं। अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि ये कीट विनाशकारी झुंड क्यों और कैसे बनाते हैं? एक अकेली टिड्डी नुकसान कम करती है। लेकिन तथाकथित अकेले रहने वाले टिड्डे एक बदलाव (मेटामोर्फोसिस) के दौर से गुजरते हैं। ये रंग बदलते हैं और लाखों अन्य टिड्डियों के साथ मिलकर तबाही मचाते हैं।

अकेले रहने वाले टिड्डे झुण्ड में कैसे बदल जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या संकेत देते हैं? इसके पीछे एक गंध संबंधी रहस्य छिपा होता है। टिड्डियों द्वारा एक ऐसी गंध छोड़ी जाती है जो आसानी से समाप्त नहीं होती है। यह इत्र की तरह एक रासायनिक यौगिक होता है। इससे वे अपनी तरह के अन्य टिड्डियों से निकटता महसूस करते हैं। यह केमिकल अन्य टिड्डियों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। टिड्डियां समूह में शामिल हो जाती हैं और खुद भी गंध का उत्सर्जन करना शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया से भारी संख्या में टिड्डियों का झुंड बन जाता है। जिसके बाद ये भारी मात्रा में फसल को बर्बाद कर दते हैं।

यह खोज कई आशावान संभावनाएं प्रदान करती है, जिसमें सूघंने की क्षमता के बिना आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग टिड्डे शामिल हैं जो कि झुंड के गंध (फेरोमोन) का पता लगाते हैं, या कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने और फंसाने के लिए गंध को हथियार बनाते हैं। यह अध्ययन नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका में टिड्डों ने भारी मात्रा में फसलों को नष्ट किया है, ये भारत, पाकिस्तान में खाद्य आपूर्ति के लिए खतरा बने हुए हैं।

गंध के रूप में कौन सा केमिकल छोड़ती है टिड्डियां?

प्रवासी टिड्डियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे कीटों की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति माना गया है, और इस दौरान अध्ययनकर्ताओं ने कीड़ों द्वारा उत्पादित कई यौगिकों की जांच भी की। अध्ययन में पाया गया कि एक विशेष रूप से 4-विनाइनिसोल,

या 4वीए (4VA)- जो एक तरह का केमिकल है, इसके उत्सर्जित होने पर टिड्डियां इसकी ओर आकर्षित होती दिखाई दिए। 4वीए के अधिक उत्सर्जन से टिड्डियों इसकी ओर अधिक आकर्षित हुई और उनका झुंड बन गया।

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर ले कांग की अगुवाई वाली टीम ने चार टिड्डियों को एक पिंजरे में एक साथ रखा और उन्होंने पाया कि टिड्डों ने एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए 4-विनाइनिसोल (4वीए) केमिकल छोड़ना शुरू कर दिया था। तब टीम ने जांच की कि कैसे टिड्डों ने गंध को महसूस किया, टिड्डी में झुंड बनाने वाले केमिकल (फेरोमोन) का पता लगाने के लिए जिम्मेदार एंटीना के हिस्से को टिड्डी से अलग कर दिया गया। उन्होंने इसे जीन का पता लगाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक बताया। आनुवंशिक रूप से संशोधित टिड्डियों का उत्पादन किया गया जिसमें मुख्य ओआर35 (OR35) जीन की कमी थी।

अध्ययन में कहा गया कि जीन में परिवर्तन (उत्परिवर्ती) किए गए टिड्डों ने जंगली प्रकार के टिड्डों की तुलना में 4वीए की ओर आकर्षित होना बंद कर दिया था, अर्थात 4वीए के प्रति उनका आकर्षण समाप्त हो गया था। इन खोजों ने फसलों को उजाड़ने वाले कीटों से निपटने के लिए कई संभावनाओं को खोला है। इनमें आनुवांशिक संशोधन का उपयोग करना, या झुंड के बनने का पूर्वानुमान के लिए 4वीए के उत्पादन पर नजर रखना शामिल है।

कांग और उनकी टीम ने क्षेत्र में दो तरह के नियंत्रित तरीके से जाल स्थापित किए, और दोनों मामलों में उन्होंने टिड्डियों को प्रभावी ढंग से लुभा कर फसाया था। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला न्यूरोएजेनेटिक्स एंड बिहेवियर के प्रमुख लेस्ली वॉशहॉल ने कहा कि शायद सबसे रोमांचक प्रयोग एक ऐसा रसायन ढूंढना होगा जो 4वीए के सूंघने (रिसेप्शन) को अवरुद्ध कर दे। इस तरह के एक अणु की खोज कीटों के झुंड बनाने को रोकने के लिए एक केमिकल ऐन्टिडोट प्रदान कर सकता है। यह टिड्डियों के झुंड बनाने को रोक सकता है और उनके शांतिपूर्ण, एकान्त जीवन के मार्ग पर लौटा सकता है। कांग ने कहा कि टिड्डियों के आनुवंशिक संशोधन से टिकाऊ उपाय किया जा सकता है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि ऐसी परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

अटल बिहारी बाजपेयी को मुख्यमंत्री ने किया याद

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। उनकी कविताएं और राजनीतिक जीवन वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

पर्यावरण अपराधः लंबित मामलों को निपटाने में लग जाएंगे 33 साल

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट बताती है कि अदालतों में 48,238 मामले लंबित पड़े हैं

2017 के मुकाबले 2018 में पर्यावरण संबंधी अपराधों में कमी आई, बावजूद इसके अदालतों में लंबित मामले बढ़ गए। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न अदालतों में लगभग 48,238 मामले लंबित पड़े हैं और जिस गति से अभी इन मामलों का निपटारा हो रहा है, अगर यही गति रही तो लंबित मामलों के निपटारे में 9 से 33 साल लग जाएंगे।

रिपोर्ट बताती है कि भले ही पूरे देश में पर्यावरण संबंधी अपराध कम हुए हों, लेकिन 12 राज्यों में ये अपराध बढ़ गए। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, मेघालय, ओडिशा, दमन दीव, दादर नागर हवेली शामिल हैं। भारत में 2017 में जहां 42,143 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2018 में 35,196 मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14,536 मामले दर्ज हुए, जबकि केरल में 5,750 मामले दर्ज हुए। हालांकि इन दोनों राज्यों में 2017 के मामले 2018 में कम मामले दर्ज हुए।

सामाजिक दूरी के साथ बीएयू में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

रांची : बिरसा कृषि विवि मुख्यालय में प्रभारी कुलपति सह कृषि सचिव अुब बकर सिद्दीकी पी ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन राकेश रोशन के साथ परेड का निरीक्षण किया व जवानों की सलामी ली. कुलपति ने कोरोना काल में विवि के निर्बाध ऑनलाइन शिक्षण कार्यो तथा अनुसंधान व प्रसार गतिविधियों की उपलब्धियों की सराहना की. विवि कर्मियों को देश हित में कृषि तकनीकी विकास एवं मार्गदर्शन से किसानों की सेवा पर जोर दिया. इससे पूर्व कुलपति सहित विवि के सभी डीन एवं डायरेक्टर्स ने परिसर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.

कृषि संकाय में डीन डॉ एमएस यादव, पशु चिकित्सा संकाय ने डीन डॉ सुशील प्रसाद तथा वानिकी संकाय में डीन डॉ एमएच सिद्दीकी ने ध्वजारोहन किया. विवि मुख्यालय एवं संकायों में सामाजिक दूरी का पालन से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. समारोह में विवि के डीन, एसोसिएट डीन, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, नियंत्रक, प्रोफेसर, सा-इंटिस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ, आकस्मिक कर्मियों एवं पीजी व पीएचडी छात्रों की मौजूदगी रही।

स्वतंत्रता दिवस पर बीएयू के प्रभारी कुलपति सह कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी पी ने कहा

कोरोना काल में बीएयू ने कृषि तकनीकी क्षेत्र में उत्साहजनक कार्य किया है

संवाददाता

रांची : कोरोना काल में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि एवं संबद्ध विषयों की शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार क्षेत्रों का कार्य काफी उत्साहजनक रहा है. विवि में कृषि, वानिकी एवं पशु चिकित्सा संकाय के 11 कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य निर्बाध जारी है. कॉलेजों के शिक्षक विद्यार्थियों से ऑनलाइन संपर्क में है. छात्रों को सेमेस्टरवार ईमेल व व्हाट्सअप पर लेक्चर नोट्स, शिक्षण सामग्री एवं शैक्षणिक परामर्श दिए जा रहे है. गूगल मीट, जूम और वेबिनार के माध्यमों से छात्रों का पठन- पाठन और जिज्ञासा समाधान किया जा रहा है.उक्त विचार बीएयू के प्रभारी कुलपति सह कृषि सचिव अुब बकर सिद्दीकी पी ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही।

कृषि संकाय के विषयों से सबंधित विभागों के लेक्चर का 138 विडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर छात्रों के पाठ्यक्रमों से अद्यतन रखने की कोशिश की जा रही रही है. इस यूट्यूब चैनल के 15 सौ से अधिक सब्सक्राइबर है. एग्रीकल्चर एवं फॉरेस्ट्री के अंडर ग्रेजुएट्स एवं पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम का रिजल्ट सही समय पर निकाला गया. छात्रों के निकटतम पशु चिकित्सा केन्द्रों में इंटर्नशिप पूरी होने पर वेटनरी के अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के छात्रों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दी जायेगी. छात्रों हित में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के विभिन्न सेमेस्टर में ऑनलाइन एडमिशन कार्य पुरा कर लिया गया है. अकादमिक कौंसिल के अनुमोदन से विद्यार्थियों की समस्यायों का समाधान किया गया है. कृषि कॉलेज के 5 सीनियर्स छात्रों ने 'एग्रीविजाड बीएयू यूटयूब चैनल' लांच कर जूनियर्स छात्रों को हायर एजुकेशन एवं एग्रीकल्चरल सर्विस की राह आसान किया. छात्रों ने 'एग्रीकैप्सूल एवं एग्री नोट्स एप' को गूगल प्लेस्टोर में डाउनलोड कर बदलते शिक्षा परिवेश का विकल्प पेश किया. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के छात्रों ने 150 किताबों युक्त 'एनरीड् नामक ई- लाइब्रेरी मोबाइल एप' से इस नये कॉलेज के छात्रों की राह आसान बना दी.

बीएयू वैज्ञानिकों ने 'झारखण्ड वेदर पोर्टल एवं एप' को बनाकर किसानों को तीन भाषाओं में 31 फसलों का मौसम पूर्वानुमान आधारित स्वचालित कृषि सलाह का मार्ग प्रशस्त किया.

अनुसंधान के क्षेत्र में करीब सभी फसलों का उन्नत किस्मों, पशु - पक्षियों के नई नस्लों तथा प्रदेश के लिए लाभकारी तकनीकों का विकास किया गया है. जो प्रदेश की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप है और इससे राज्य में अधिक खाद्यान उत्पादन को बढावा मिला है.

पशुपालन, मछली पालन, मधुमख्खी पालन, वानिकी, कृषि वानिकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में लाभकारी तकनीकों को ईजाद किया गया है. इससे राज्य के किसान खुशहाल हो रहे हैं.

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा प्रभावी ढंग से किसानों को नियमित रूप से परामर्श दे रहा है. इसे किसान हित में व्यापकता देने की जरूरत है. वैज्ञानिकों को बदलते मौसम को ध्यान में रख काफी सट-ीक शोध कार्य करने की आवश्यकता है. ताकि विषम मौसम परिस्थितियों के प्रभाव और कृषि जोखिम में कमी लाई जा सके.

कृषि एवं सम्बद्ध विषयों के प्रसार में विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा है. आईसीएआर की आठ वर्षीय समीक्षा दल ने प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों की सराहना की है. आईसीएआर की 'फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम' में किसानों की भागीदारी से कृषि आय में इजाफा को बल मिला है. 5.33 करोड़ लागत की आईसीएआर - क्षमता प्रसार परियो जना में 10 आदिवासी बहुल जिलों में मधुमख्खी, सूकर एवं बकरी पालन कार्यक्रमों से आजीविका और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिला है. मशरूम उत्पादन, फसल उत्पादों का प्रोसेसिंग एवं मूल्यवर्धन, गृह वाटिका, सूकर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं मधुमख्खी पालन विषयों के प्रशिक्षणों से आजीविका एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया. कोरोना काल में रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन 40 किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग तथा कॉमन सर्विस सेंटर के तहत प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से ग्राम एवं पंचायत स्तर पर किसानों को ट्रेनिंग एवं समस्या समाधान किया जा रहा है.

कृषि विज्ञान केन्द्रों के ट्रेनिंग, एफएलडी, ओएफटी, सीएफएलडी, सीड विलेज, पल्स सीड हब, बीज एवं पौध सामग्री उत्पादन, साइल हेल्थ, मौसम आधारित निकरा परियोजना आदि कार्यक्रमों से जिलों में कृषि विकास को गति मिली है. कोरोना काल में विभिन्न एजेंसियों से प्रसार परियोजनाओं की स्वीकृति एक उल्लेखनीय उपलब्धि हैं. केवीके माध्यम से 16 जिलों में अनूसूचित जाति के किसानों के जीविकोपार्जन में सुधार हेतु आईसीएआर ने 4 करोड़ लागत की योजना, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से 4 आकांक्षी (पिछड़े) जिलों के किसानों के विकास के लिए 1.92 करोड़ लागत की योजना तथा आईसीएआर - भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, झाँसी से अनूसूचित जाति किसानों द्वारा 5 जिलों में चारा फसलों के विकास की 20.57 लाख लागत की योजना स्वीकृत मिली है. सीमित मानव बल एवं संसाधनों के बावजूद कोरोना काल में उपलब्धियाँ बेहद उत्साहजनक है ।

राज्यपाल ने चेतन चौहान के निधन पर शोक प्रकट किया

रांची : राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि चेतन चौहान एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, कमेंटेटर के साथ-साथ कुशल एवं प्रखर वक्ता और जननेता थे जो लोगों से निरंतर जुड़े रहते थे।

राज्यपाल महोदया ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें।

सीएमपीडीआई : कोयलाधारक क्षेत्र बढ़ कर 32760 वर्ग किमी हुआ

रांची :वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएमपीडीआई और जीएसआई के संयुक्त प्रयास ने देश के पूर्ववर्ती कोयला धारक क्षेत्र को 19400 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 62 कोयला क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 32760 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कोयला धारक क्षेत्र में 59 प्रतिशत की वृद्धि से देश के लगभग 13700 वर्ग किलोमीटर में कोयला उत्खनन गतिविधियों का विस्तार होगा और भविष्य में देश के कोयला एपेटाइट (कोयले की जरूरत) को पूरा करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 292 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का विस्तृत गवेषण के जरिए लगभग 7.77 बिलियन टन कोयला संसाधन को प्रमाणित श्रेणी में जोड़ा गया, जो सीएमपीडीआई द्वारा अपने स्थापना काल से 1 वर्ष में अब तक सर्वाधिक प्राक्कलित कोयला संसाधन है। 140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रोमोशनल गवेषण के जरिए लगभग 9.75 बिलियन टन नए संसाधन का आकलन किया गया। 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात अपने अभिभाषण में उक्त बातें सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेश-ाक एस0 सरन ने कही। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी/ईएस) के0के0 मिश्रा, निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडी) आर0एन0झा, निदेश-ाक (तकनीकी/पीएंडडी) ए0के0 राणा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0के0 गोमास्ता, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमीत कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक-क्षेत्रीय संस्थान-3-मनोज कुमार सहित सीएमपीडीआई परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मना स्वतंत्रता दिवस समारोह

संवाददाता

रांची :मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण किया । इस अवसर पर उन्होंने मंडल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी । उनहोंने कहा कि मंडल से अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक कुल 0 .80 मिलियन टन लोडिंग हुआ जिससे मंडल को 65 .26 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, मंडल के सात स्टेशनों पर नए शौचालय बनाए गए, नामकुम गुड्स शेड को सर्व सुविधा युक्त किया गया, रांची मंडल के सभी स्टेशनों पर निशुल्क वाई - फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई , कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु 12800 फेस मास्क, 2000 फेस शील्ड एवं 4950 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया, रांची रेलवे स्टेशन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम की स्थापना, लॉकडाउन अवधि में कुल 70,000 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने इस अवसर पर उपस्थित सभी रेल कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सिविल डिफेंस के 14, संत जॉन एम्बुलेंस के 19 तथा चिकित्सा विभाग के 13 कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने कोरोना वारियर का प्रशंसनीय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

परियोजना प्रभावित परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध

सीएमडी ने कहा :मगध-आम्रपाली क्षेत्र में सीएसआर के अंतर्गत किए जा रहे हैं कई जन-कल्याण कार्य

रांची : सीसीएल शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, रोजगार, आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं ये बाते सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने कही उन्होंने कहा कि सीसीएल मुख्य प्राथमिकता ' 'गरीब, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास है। सीसीएल क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और यह विश्वास दिलाता है कि आगे भी कल्याणकारी योजनाओं और तेजी से क्रियान्वयन किया जायेगा।

मगध-आम्रपाली क्षेत्र के 51 परियोजना प्रभावित बच्चों को गोद लिया गया है, जिन्हे संत जोसेफ स्कूल, मंडेर और संत थॉमस स्कूल, टंडवा मेंहॉस्टल की सुविधा के साथ शिक्षा मुहैया करायी जा रही है। सीसीएल द्वारा शिक्षा से संबंधित खर्च यानि स्कूल फीस, हॉस्टल फीस, किताबें, स्टेशनरी आदि का भुगतान सीएसआर के तहत किया जा रहा है। साथ ही सीएसआर पहल के अंतर्गत परियोजना प्रभावित ग्रामीणो के बच्चों को स्कूल आनेजाने के लिए 52 सीट वाली02 (दो) स्कूल बस (वाहन) का परिचालन किया जा रहा है, एक बस आम्रपाली परियोजना के बच्चों और दूसरी मगध परियोजना के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गयी है। इन बसों का उद्घाटन सिमरिया विधायक किशुन दास ने किया गया दोनों परियोजना के विस्थापित गांवों के विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों में 387 डेस्क एवं बेंचों का वितरण किया गया है। विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणो को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सीसीएल प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 40 सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल का स्थापित किये गए हैं।

सीसीएल ने 51 बच्चों को गोद लिया है

सीसीएल का कहना है कि अब तक मगध परियोजना में 325 एवं आम्रपाली परियोजना में 77 विस्थापितों को भूमि के बदले सीसीएल में स्थायी नौकरी प्रदान की जा चुकी है । इसके अलावा सीसीएल प्रबंधन की अनुशंसा के आधार पर आउटसोर्शिंग कंपनियां मगध परियोजना में 418 एवं आम्रपाली परियोजना में 700 प्रभावित एवं विस्थापित रैयतों को उनकी दक्षता (कुशल व अकुशल) के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया है। उत्पादन एवं प्रेषण कार्यों में भी रोजगार के अन्य अवसर का सृजन हो रहे हैं जिससे स्थानीय ग्रामीण अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सीसीएल चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा विभिन्न विस्थापित गांवों में नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमे ग्रामीणों की नि:शुल्क जांच, चिकित्सीय परामर्श के साथ-साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है` आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मगध-आम्रपालीपरियोजनाओं में एक - एक नया एम्बुलेंस सीएसआर के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है ।

रांची रेल मंडल में स्वच्छता सप्ताह अभियान चला

रांची रेल मंडल में दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 14 अगस्त 2020 को मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज अम्बष्ठ के नेतृत्व में रांची रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता शपथ ली गई तथा स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया तथा प्लेटफार्म पर सफाई की गई।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उनका भी निरीक्षण किया गया।

इस अभियान में अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, रांची रेल मंडल के डीआर यूसीसी सदस्य श्री नवजोत अलंग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीसी हेंब्रम, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

हटिया रेलवे स्टेशन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा)अजीत सिंह यादव के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चलाया गया अभियान में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया तथा प्लेटफार्म पर सफाई की गई इस अभियान में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता श्री एस उरांव, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरडी) ए आर दास, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी चैतन्य सिंग एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भाग लिया तथा मंडल के सभी स्टेशनों एवं कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त 2020 को स्वच्छता संवाद एवं सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें कर्मचारियों तथा कॉलोनी के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

लगातार कम हो रहे है साइकैड के पौधे

एजेंसियां

पारिस्थितिकी तंत्र में साइकेड के पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि साइकैड पौधों की दो प्रजातियां मिट्टी के माध्यम से नाइट्रोजन और कार्बन को साझा करती हैं, जिससे अन्य जीवों को लाभ होता है

साइकैड बहुत लंबे जीवाश्म इतिहास वाले पौधों में से एक हैं। ये आज की तुलना में पहले बहुत अधिक पाए जाते थे। साइकैड के पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में साइकैड का प्रतिनिधित्वसाइकस वंश द्वारा किया जाता है जिसमें 12 प्रजातियां शामिल हैं।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि साइकैड के पौधे लगातार कम हो रहे हैं। दुनिया भर में ये पौधे सबसे अधिक खतरे वाले समूह में हैं। ये पौधे अपने पड़ोसी जीवों को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि कम से कम दो साइकैड पौधों की प्रजातियां मिट्टी के माध्यम से नाइट्रोजन और कार्बन को साझा करती हैं, जिससे अन्य जीवों के लिए वहां रहने योग्य वातावरण का निर्माण होता है।

अमेरिका की मॉन्टगोमरी बॉटनिकल सेंटर के कार्यकारी निदेशक पैट्रिक ग्रिफिथ ने कहा कि इस अध्ययन से पता चलता है कि प्राकृतिक आवासों से साइकैड के पौधों को होने वाले नुकसान से खतरनाक प्रभाव पैदा होता है। जिससे अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव साइकैड के पौधों के पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर करते हैं। यह अध्ययन

हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। साइकैड के पौधे अपने विशेष जड़ों के भीतर नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया की मेजबानी करते हैं। सूक्ष्मजीव इच्छानुसार नए अर्जित किए गए नाइट्रोजन को आपस में साझा करते हैं जिससे खुद को और मिट्टी के जीवों दोनों को फायदा होता है।

वेस्टर्न पेसिफिक ट्रॉपिकल रिसर्च सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर एड्रियन एरेस के अनुसार, गुआम विश्वविद्यालय में शोध दल लंबे समय से अपने स्थानीय सीमा में साइकस माइक्रोनिका के पोषक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। एरेस ने कहा कि इस अनोखे पेड़नुमा (आर्कियोसेन्ट) साइकैड प्रजाति के पौधे का सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व है। यह पौधों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में नई जानकारी को उजागर करता है। अध्ययन मिट्टी में तीन तत्वों के मिश्रण पर केंद्रित है जो जीवित जीवों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। साइकैड के पौधे अपने आस-पास की मिट्टी में, नाइट्रोजन और कार्बन की सांद्रता को संतुलित करते हैं। साइकैड के पौधे मिट्टी में फास्फोरस की सांद्रता को भी संतुलित करते हैं।

एरेस ने कहा कार्बन और नाइट्रोजन के प्रत्यक्ष योगदान के अलावा, साइकैड के पौधों द्वारा किए गए रासायनिक परिवर्तनों ने दूसरों के लिए अन्य पौधों के उगने, सूक्ष्मजीवों के जीने के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया। यह सब जंगलों में स्थानीय विविधता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। एरेस ने आगे जोड़ते हुए कहा, उच्च जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र आम तौर पर अधिक प्रतिरोधी होते हैं। जो खतरों से होने वाले नुकसान और बुरे प्रभावों को सहन कर लेते हैं। साइकैड के पौधों द्वारा दूसरे जीवों, पौधों के लिए बनाए गए स्थान मिट्टी के खाद्य जाल को एक सूक्ष्म आवास (माइक्रोहैबिटैट) प्रदान करते हैं जो आस-पास के जंगल की मिट्टी से भिन्न होता है।

साइकैड के पौधे मिट्टी में उन सूक्ष्मजीवों को फायदा पहुंचाते हैं जिन्हें फास्फोरस की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन और अधिक कार्बन स्तर की जरुरत होती है। वैज्ञानिक इन मौलिक संबंधों को "स्टोइकोमेट्री" कहते हैं, और जीवों के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए इन संबंधों के महत्व के बारे में बहुत अध्ययन किया गया है। स्टोइकोमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया में विभिन्न उत्पादों और अभिकारकों के द्रव्यमान की संख्या के बीच मात्रात्मक संबंध है। अध्ययन में मॉडल साइकैड के पौधों की दो प्रजातियां शामिल की गईं थी।

फोटो न्यूज

झारखंड की पहचान एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का घना सारंडा जंगल

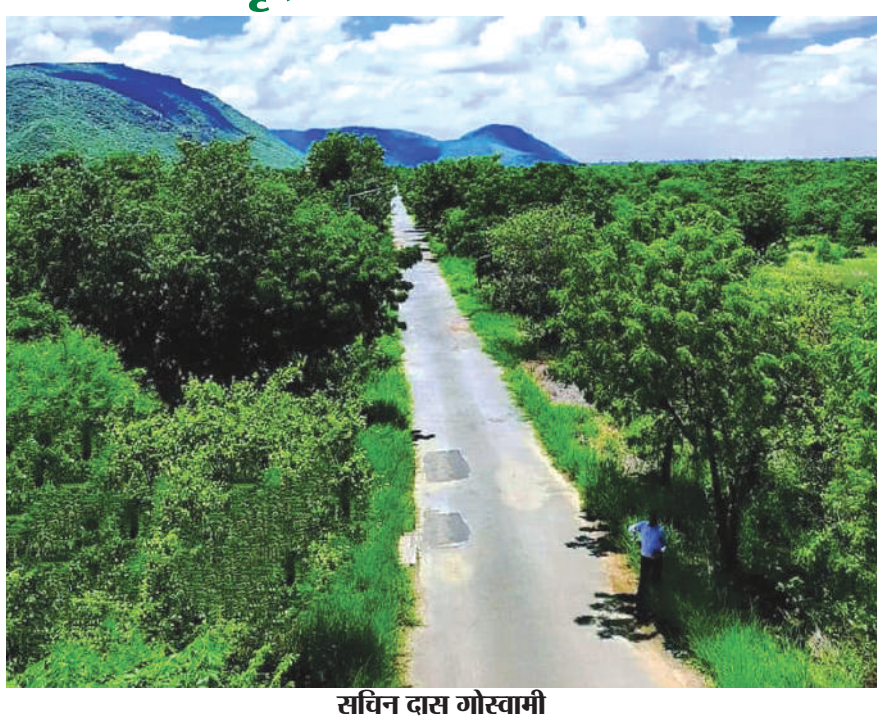

सचिन दास गोस्वामी

झारखण्ड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है।सारंडा का अर्थ होता है सात सौ पहाड़ियां`सारंडा का कुछ हिस्सा उड़ीसा एवं छतीसगढ़ की सीमा से भी सटा है। विहंगम सात सौ पहाड़ियों से घिरा यह वन पूरे एशिया में साल (सखुआ) वृक्ष की अत्याधिक संख्या के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ बांस,जामुन,कटहल ,आम एवं पलाश के भी अनेकों पेड़ है।खामोशी में डूबे इस जंगल में हरियाली और खूबसूरती का बेजोड़ मेल देखने को मिलता है। ऊँचे, छांवदार, फलदार इन अनगिनत पेड़ो का वर्चस्व यहां कुछ ऐसा है कि सूरज की किरणें भी आने से घबराती है। वहीं पलाश के सुर्ख लाल फूल जब यहां की धरती को छूते है तो लगता है कि किसी ने लाल कालीन बिछा दिया हो।हमारे देश में यह एक ऐसा अनोखे स्थान है जहां की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान काफी समृद्ध है। ऐसे में अगर आप खूबसूरत झरनों, पहाड़ों एवं घने जंगलों में घूमने के शौकिन है तो सारंडा के जंगल आपके लिए उपयुक्त जगह है।खूंटी जिला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हिरनी जलप्रपात हिरनी नामक गांव में स्थित है। हिरनी फाल्स घूमने के अलावा पर्यटक 3 किलोमीटर दूर बने डियर पार्क एवं 3.5 किलोमीटर दूर स्थित खूबसूरत यॅक गार्डन का मजा भी ले सकते है। प्रकृति के अद्भूत नजारे से भरपूर सात सौ पहाड़ियों एवं घने जंगलो का यह घर विहंगम दृश्यों और रोमांच से भरा है।

अत्याधुनिक तकनीकी पर करना होगा फोकस

अनेक विरल प्रजाति के जंगली पशु पक्षी, सरीसृप, वृक्षलता भी जंगल की कटाई और मैनिंग से नष्ट हो जा रहे हैं। राज्य की जंगल संपदा को बचाना होगा। राज्य सरकार को इस दिशा में प्रयत्नवान होना उचित हैइसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीकी पर भी फोकस करना होगा। केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहने से यह सब नही हो पाएगा। इसके लिए आम लोगों का भी सहयोग जरूरी है।

जल एक नि:शुल्क औषधी है

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

"जल ही जीवन है "ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं लेकिन इस बात में बहुत गहराई है।हमारे शरीर में लगभग 70 फीसदी जल की मात्रा होती हैं ,इसलिए उसे बनाये रखने के लिए और शरीर के आंतरिक अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हमे नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम से कम से कम 2 से तीन लीटर पानी रोज पानी चाहिए।उम्र और वज़न कारण पानी पीने के मात्रा मे बदलाव आ सकता है। जितना बाहरी शरीर को साफ करने के लिए हमे पानी की आवश्यकता होती है उतनी ही आंतरिक अंगों के लिए पानी आवश्यक है। पानी एक निशुल्क औषधि है जो हमें स्वस्थ और तरोताज़ा रखता है।

■पानी हमारे शरीर और दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है।

■ऊर्जा के स्तर को बढ़ता है और हमे चुस्त और फुर्तीला रखता है।

■भोजन के पाचन क्रिया में पानी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कम पानी पानी से पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं।

■अस्थमा, उच्च रक्तचाप और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी काफी सुधार होता है ,अगर पानी प्रचुर मात्रा में पीया जाये।

■पानी पीने से शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई होती हैं,ये हानिकारक पदार्थों को मूत्र द्वारा बाहर निकल देता है।

■सुबह के समय खाली पेट पानी पीने से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है।

■गुनगुना पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ,और त्वचा और बाल स्वस्थ रहते है।अगर सम्भव हो तो दिन-भर आप गुनगुने पानी का ही सेवन करे।

■अच्छे मात्रा मे पानी पीने से गुर्दे की समस्या नहीं होती हैं और अगर गुर्दे में पथरी की समस्या हो तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है।

■गुनगुने पानी के सेवन से एसिडिटी की समस्या से भी काफी सुधार होता है।

■शरीर को हाइड्रेट रखता है और एक प्र-कृति कालिंजर के जैसे काम करता है जो अंदर और बाहर से शरीर को साफ रखता है।

पानी प्रकृति के द्वारा वो देन है जो किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए इसका भरपूर उपयोग तो करना ही चाहिए साथ साथ इसको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। याद रहे जल है तो कल है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

जम्मू और कश्मीर में रेत खनन पर1.57 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव की ओर से रेत खनन पट्टे (लीज) के मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों से पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना कोई खनन पट्टे (लीज) नहीं दिए गए है।

जम्मू और कश्मीर में रेत खनन की बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि यहां नदियों के किनारे और तल पर बहुत कम रेत होती है। खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी की वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद जिला डोडा में केवल एक रेत खनन पट्टा (लीज) दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में वन क्षेत्रों में रेत खनन की कोई घटना नहीं हुई है। लघु खनिजों के अवैध निकासी, इसको वाहनों द्वारा इधर-उधर ले जाने पर अंकुश लगाने और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से रोकने के लिए, जियोलॉजी और खनन विभाग ने मजबूत निगरानी तंत्र बनाया है। निगरानी में वाहनों, मशीनों, डंपरों की नियमित जांच करना तथा इनको जब्त करना शामिल है। अब तक लगभग 3684 वाहन अवैध खनन में लिप्त पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार इन पर 1.57 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

ध्वनि प्रदूषण की निगरानी को दिल्ली में बनी कमेटी

एजेंसियां

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर 11 अगस्त को एक निगरानी समिति गठन करने का निर्देश दिया। समिति उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के अनुपालन की स्थिति का पता लगाने, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के संबंध में सुझाव देगी।

अदालत ने कहा कि भले ही दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कुछ कदम उठाए गए हों - लेकिन ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। आदेश में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण मानकों को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

एनजीटी द्वारा मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से साप्ताहिक आधार पर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है।

रोरो गांव में अभ्रक खदानों से उड़ रही धूल से स्वास्थ्य और पर्यावरण को हो रहा है नुकसान

रोरो गांव में अभ्रक की पुरानी खदानों से उड़ रही धूल के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को हो रहा है नुकसान झारखंड सरकार द्वारा एनजीटी को रोरो अभ्रक खदान, चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र की बहाली के लिए उठाए गए कदमों की सूची देने से पहले एक रिपोर्ट सौंपी गई।

इस तरह की खदानों के लिए लीज हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट लिमिटेड (एचएसीपीएल) के पक्ष में दी गई थी। वर्ष 1983 में खदानों ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि, इस क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, खदानों के पुनर्स्थापन के लिए सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे।

स्वास्थ्य को होने वाले खतरों, तालाबों और नदियों के प्रदूषण के परिणामस्वरूप एस्बेस्टस धूल आधारित प्रदूषण का उत्सर्जन लगातार जारी रहा। ट्रिब्यूनल को झारखंड राज्य द्वारा सूचित किया गया था कि रोरो गांव की छोड़ी गई अभ्रक की खदानों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास से संबंधित कई योजनाएं लागू की गई थीं।

योजनाओं में 'बड़ा लागिया पंचायत के अंदर रोरो गांव के मुंडसई' में एक जल मीनार का निर्माण शामिल है। 565 स्थानीय निवासियों की स्वास्थ्य जांच (1,50,000 रुपये की लागत से प्रारंभिक जांच) की गई थी। 565 स्थानीय निवासियों में से 164 में एस्बेस्टोसिस बीमारी के लक्षण पाए गए थे। 164 स्थानीय निवासियों में से 126 का पीपीटी और एक्स-रे परीक्षण किया गया था।

मोहक सुगंध होती है पारिजात या हरसिंगार की

मुरलीधर

श्रीमदभगवत गीता के दशम स्कन्ध के 59 वें अध्याय के 39 वें श्लोक में पारिजात वृक्ष का उल्लेख पारिजात हरण नरकवधों नामक अध्याय में की गई है।

परिजात वृक्ष दैवीय है

ईश्वर की आराधना में फूलों का विशेष स्थान है। फूल, पवित्र और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं इसलिए देवताओं को यह खूब भाते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में रंग-बिरंगे अनेक फूल मौजूद हैं, जिनमें से एक है परिजात का फूल।

परिजात का फूल देखने में अलौकिक प्रतीत होता है लेकिन इसके उद्भव से जुड़ी कहानी इससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत है। परिजात के वृक्ष की खासियत है कि जो भी इसे एक बार छू लेता है उसकी थकान चंद मिनटों में गायब हो जाती है। उसका शरीर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है।

हरिवंशपुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी परिजात के वृक्ष को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। परिजात के वृक्ष को दैवीय कहा जाता है, जिसमें साल में बस एक ही महीने में फूल खिलते हैं। गंगा दशहरा के आसपास यह पेड़ फूल खिलाता है लेकिन हैरानी की बात है जब पेड़ से फूल झड़ते हैं तो

वे पेड़ के करीब नहीं,बहुत दूर जाकर गिरते हैं। परिजात के फूलों का यह स्वभाव भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा है।

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इन्द्रलोक से इस वृक्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने ये फूल उनसे लेकर अपने निकट बैठी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। इस घटना के बाद नारद, कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि परिजात के बेहद खूबसूरत फूल कृष्ण ने रुक्मिणी को सौंप दिए और उनके लिए एक भी नहीं रखा। यह बात सुनकर सत्यभामा ईर्ष्या से भर गईं और कृष्ण से जिद करने लगीं कि उन्हें परिजात का दिव्य वृक्ष चाहिए। परिजात का वृक्ष देवलोक में था, इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा कि वे इन्द्र से आग्रह कर वृक्ष उन्हें ला देंगे। पति-पत्नी में झगड़ा लगाकर नारद, देवराज इन्द्र के पास गए और उनसे कहा कि मृत्युलोक से इस वृक्ष को ले जाने का षडयंत्र रचा जा रहा है लेकिन यह वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, इसलिए यहीं रहना चाहिए। इतने में ही कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इन्द्रलोक आए। पहले तो इन्द्र ने यह वृक्ष सौंपने से मना कर दिया लेकिन अंततः उन्हें यह वृक्ष देना ही पड़ा।

जब कृष्ण परिजात का वृक्ष ले जा रहे थे तब देवराज इन्द्र ने वृक्ष को यह श्राप दे दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। सत्यभामा की जिद की वजह से कृष्ण परिजात के पेड़ को धरती पर ले आए और सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया। लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में था लेकिन इसके फूल रुक्मिणी की वाटिका में गिरते थे।

इस तरह सत्यभामा को वृक्ष तो मिला लेकिन फूल रुक्मिणी को ही प्राप्त होते थे। यही वजह है कि परिजात के फूल, अपने वृक्ष से बहुत दूर जाकर गिरते हैं।

पारिजात या हरसिंगार के वृक्ष में कई औषधीय गुण भी होते हैं। बुखार के इलाज में इसके पत्तों का उपयोग आम है साथ ही कई अन्य रोगों में इसके पुष्प को खाने से बहुत ही लाभ मिलता है।

अक्षय ऊर्जा दे सकती है भारत-नेपाल के रिश्तों को मजबूती

एजेंसियां

भारत, नेपाल, भूटान, और बांग्लादेश के बीच अक्षय ऊर्जा व्यापार हानिकारक जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन की जगह ले सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग केवल बाजार सम्बन्धी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय स्तर की क्रांति है। भारत, नेपाल, भूटान, और बांग्लादेश के बीच अक्षय ऊर्जा व्यापार हानिकारक जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन की जगह ले सकता है और विशाल हाइड्रो-पावर संभावना के साथ नेपाल भारत के ऊर्जा संतुलन सम्बन्धी मांग को आसानी से पूरा कर सकता है।

इंटीग्रेटेड रिसर्च ऐंड ऐक्शन फॉर डेवलपमेंट के तकनीकी निदेशक वीके अग्रवाल ने भारत-नेपाल के बीच दिवपक्षीय व्यापार की संभावनाओं को लेकर यह बात कही। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) ने शुक्रवार को 'भारत-नेपाल सब-नेशनल एनर्जी ट्रेड' को प्रोत्साहन देने के लिए "पावरिंग इंडिया-नेपालः लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे थ्रू ट्रांस बाउंड्री रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच साझा मुद्दों और ऊर्जा व्यापार के अवरोधों की पहचान करना तथा एक समुचित नीतिगत ढांचे पर विचार करना था, जिससे ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में परस्पर लाभ हो और दक्षिण एशिया के ये दोनों देश भी सतत विकास के पथ पर अग्रसर हों। इस वेबिनार में भारत और नेपाल से बिजनेस लीडर्स, रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपर्स, थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड, नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और इंडेपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल के उपाध्यक्ष कुमार पांडे ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय एजेंसियों ने अंतर्देशीय व्यापार को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। अब हम ऐसी अवस्था में हैं, जब ऊर्जा बाजार द्विपक्षीय व्यापार के लिए अनुकूल है। इसलिए गतिरोध के मुद्दों को सुलझा कर ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में नए युग में प्रवेश करने का यह सही समय है। इससे सभी स्टेकहोल्डर्स को फायदा होगा।

हाइड्रो सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञाननेद्र लाल प्रधान ने वेबिनार में अपनी बात रखते हुए कहा कि ''हाइड्रो पावर कोई विकल्प नहीं, बल्कि विवशता है और एक मजबूत साधन है, जो बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कारगर होगा। नेपाल से हाइड्रो पावर के निर्यात की असीम संभावनाएं हैं और यह क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वेबिनार का संचालन करते हुए अभिषेक प्रताप (एनर्जी एक्सपर्ट, असर) ने कहा कि "जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कारगर ढंग से रोकने में अक्षय ऊर्जा की बड़ी भूमिका है, और इन ऊर्जा विकल्पों को सीमाओं तक सीमित नहीं रख कर सबको साझा किया जाना चाहिए। भारत-नेपाल अक्षय ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के ऊर्जा संबंधी आकांक्षाओं और मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आधारभूत संरचना को तैयार करने तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने के साथ-साथ दोनों देशों में सरकारों, बिजनेस संगठनों और अन्य पक्षों के बीच आपसी विश्वास को और सुदृढ़ करने की जरूरत है।

इसके अलावा जो मुद्दे उभर कर सामने आये, उनमें एक द्विपक्षीय कानूनी और नियामकीय ढाँचे, नेपाल भारत और बांग्लादेश के बीच एक ग्रिड, तथा 'रीजनल एंसीलरी मार्केट' की जरूरत प्रमुख रहे। नेशनल एनर्जी ट्रेड के तहत अक्षय ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समुचित माहौल में मजबूत नीतिगत पहल और नियामकीय ढांचे की जरूरत है, जिससे कि अवरोधों को दूर कर साझा मुद्दों पर सहमति बन सकें और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशा जा सके। इससे द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे और कम कार्बन उत्सर्जन से ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

E ZONE CARE

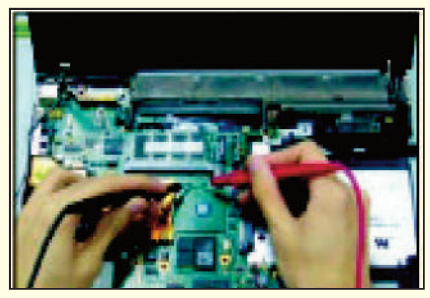

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।